>

Title: Problems being faced by the people in Jharkhand due to partisan attitude of the Union Government.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रहिम का एक दोहा है कि रहिमन वे नर मर चुके, जे कहीं मांगन जाई, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाई। मैं झारखंड के जिस राज्य से आता हूं,...(व्यवधान) हम आपसे मांगने के लिए आए हैं, केन्द्र सरकार से मांगने आए हैं और समस्या यह है कि हम मांगने आए हैं, आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम इतना माइंस और मिनरल्स प्रोडयूस करते हैं, यदि झारखंड इस देश में न हो तो मुझे लगता है कि जो नौ परसैंट ग्रोथ है, वह कभी पूरी नहीं हो सकती है, चाहे कोयला, ऑयरन-ओर या बाक्साइट का सवाल हो। वहां की विडम्बना यह है कि 24 जिलों में से 14 जिले इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में है, इसका मतलब पूरा का पूरा नक्सलाइट है। आठ जिले ऐसे हैं, जोकि राज्य सरकार मांग रही है कि हमें आप इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में डाल दीजिए। इसका मतलब संपूर्ण झारखंड इंटीग्रेटेड प्लान में है। 70 परसैंट महिलाएं एनेमिक हैं और 60 परसैंट बच्चे जो तीन साल से छोटे हैं, वे माल न्यूट्रीशन के शिकार हैं, आप समझ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि इनका डेवेलपमेंट तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि आप उन्हें कनेक्टीविटी न दें और कनेक्टीविटी यह है कि हम सबसे ज्यादा रेलवे, माइंस और मिनरल्स के लिए रेवेन्यू देते हैं। यदि रेलवे को सबसे ज्यादा पैसा आता है तो हमारे राज्य से आता है। यदि नेशनल हाईवे ऑथोरिटी सबसे ज्यादा पैसा कमाती है तो हमारे से कमाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान मंत्री सड़क योजना का रोड नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है। अभी जो दस हजार किलोमीटर ये नेशनल हाईवे बनाने वाले हैं, उसमें राज्य को केवल ये तीन सौ किलोमीटर देने वाले हैं।

सभापति महोदया, आपको आश्चर्य होगा कि हमने छ: प्रोजेक्ट में, बिहार और बंगाल जो हमारे बगल में सटा हुआ है, उसका सारा का सारा प्रोजेक्ट का फंडिंग रेलवे अपने पैसे से कर रही है। लेकिन हमारे जैसे राज्य से, जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू रेलवे को दे रहा है, 6 ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं, जिनमें कि 60-70 परसेंट पैसा हम दे रहे हैं, वे प्रोजैक्ट्स भी 5-6 साल डिले चल रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि हमारे चूंकि 26 परसेंट गांव ही अभी तक कनैक्ट हो पाये हैं, इसलिए आप प्रधानमंत्री सड़क योजना से हमारे राज्य को रोड दीजिए। नेशनल हाईवे में हमारी जो स्थिति है, उसको बढ़ाइये और रेलवे के जो प्रोजैक्ट्स पैंडिंग हैं, जिनमें कि 67 परसेंट पैसा हमारा है, उसके एम.ओयू. को आप 50 परसेंट पर करिये और नये रेलवे प्रोजैक्ट्स करिये, इसी से भला होगा।